



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-27062022-236829
CG-DL-W-27062022-236829

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 25] नई दिल्ली, जून 19—जून 25, 2022, शनिवार/ज्येष्ठ 29—आषाढ़ 4, 1944
No. 25] NEW DELHI, JUNE 19—JUNE 25, 2022, SATURDAY/ JYAISTHA 29—ASADHA 4, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 3 जून, 2022

का.आ. 578.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री राजकिरण राय जी. के स्थान पर सुश्री ए. मणिमेखलई (जन्म तिथि: 4.3.1966), कार्यपालक निदेशक, केनरा बैंक को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूनियन बैंक आफ इंडिया में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एंड सीईओ) के पद पर नियुक्त करती है।

[ई. फा. सं. 4/4/2021-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 3rd June, 2022

S.O. 578.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Ms A. Manimekhalai (DoB: 4.3.1966), Executive Director, Canara Bank as Managing Director and Chief Executive Officer (MD & CEO) in Union Bank of India for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier, *vice* Shri Rajkiran Rai G.

[eF. No. 4/4/2021-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जून, 2022

का.आ. 579.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री एस. कृष्णन के स्थान पर श्री स्वरूप कुमार साहा (जन्म तिथि: 8.2.1967), कार्यपालक निदेशक, पंजाब नैशनल बैंक को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब एंड सिंध बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एंड सीईओ) के पद पर नियुक्त करती है।

[ईफा. सं. 4/4/2021-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd June, 2022

S.O. 579.— In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Central Government hereby appoints Shri Swarup Kumar Saha (DoB: 8.2.1967), Executive Director, Punjab National Bank as Managing Director and Chief Executive Officer (MD & CEO) in Punjab & Sind Bank for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier, *vice* Shri S. Krishnan.

[eF. No. 4/4/2021-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 जून, 2022

का.आ. 580.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 19 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के उप-प्रबंध निदेशक (डीएमडी) श्री आलोक कुमार चौधरी (जन्म तिथि: 6.6.1964) को पदभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी अधिवर्षिता की आयु (अर्थात् 30.6.2024) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक (एमडी) के पद पर नियुक्त करती है।

[ईफा. सं. 2/1/2021-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 7th June, 2022

S.O. 580.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 19 read with sub-section (1) of section 20 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, hereby appoints Shri Alok Kumar Choudhary (date of birth: 6.6.1964), Deputy Managing Director (DMD), State Bank of India (SBI) as Managing Director (MD) in State Bank of India with effect from the date of assumption of office and up to the date of his superannuation (*i.e.* 30.6.2024), or until further orders, whichever is earlier.

[eF. No. 2/1/2021-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

का.आ. 581.— भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री वेणु श्रीनिवासन (जन्म तिथि: 11.12.1952) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[ईफा. सं. 6/6/2022-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 14th June, 2022

S.O. 581.— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby nominates Shri Venu Srinivasan (DOB: 11.12.1952) as part-time Non-official Director on the Central Board of Reserve Bank of India for a period of four years from the date of notification of his appointment, or until further orders, whichever is earlier.

[eF. No. 6/6/2022-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

का.आ. 582.— भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, डॉ. रविन्द्र एच. डोलकिया (जन्म तिथि: 2.4.1953) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[ईफा. सं. 6/6/2022-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 14th June, 2022

S.O. 582.— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby nominates Dr Ravindra H. Dholakia (DOB: 2.4.1953) as part-time Non-official Director on the Central Board of Reserve Bank of India for a period of four years from the date of notification of his appointment, or until further orders, whichever is earlier.

[eF. No. 6/6/2022-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

का.आ. 583.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री पंकज रमनभाई पटेल (जन्म तिथि: 16.3.1953) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[ईफा. सं. 6/6/2022-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 14th June, 2022

S.O. 583.— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby nominates Shri Pankaj Ramanbhai Patel (DOB: 16.3.1953) as part-time Non-official Director on the Central Board of Reserve Bank of India for a period of four years from the date of notification of his appointment, or until further orders, whichever is earlier.

[eF. No. 6/6/2022-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

का.आ. 584.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री आनंद गोपाल महिन्द्रा (जन्म तिथि: 1.5.1955) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[ईफा. सं. 6/6/2022-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 14th June, 2022

S.O. 584.— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby nominates Shri Anand Gopal Mahindra (DOB: 1.5.1955) as part-time Non-official Director on the Central Board of Reserve Bank of India for a period of four years from the date of notification of his appointment, or until further orders, whichever is earlier.

[eF. No. 6/6/2022-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जून, 2022

का.आ. 585.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (2) के उपबंध पंजाब नैशनल बैंक पर लागू नहीं होंगे, जहां तक इसका संबंध मिलेनियम सिटी एक्सप्रेसवेज प्राइवेट लिमिटेड की चुकता पूंजी के 30% से अधिक की राशि की इसकी शेयरधारिता से है।

2. यह छूट 31 मार्च, 2023 या इसके प्रतिसंहरित होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगी।

[फा. सं. 7/6/2022-बीओए-1]

ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 16th June, 2022

S.O. 585.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declare that the provision of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply to Punjab National Bank, in so far as they relate to its holding shares of an amount exceeding thirty per cent. of the paid-up capital of Millenium City Expressways Private Limited.

2. This exemption shall be in force until 31st March, 2023 or till its revocation, whichever is earlier.

[F. No. 7/6/2022-BOA-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

**विदेश मंत्रालय
(सी.पी.वी. प्रभाग)**

नई दिल्ली, 16 जून, 2022

का.आ. 586.—राजनयिक और कौंसुलीय अधिकारी (शपथ एवं फीस) के अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में वैधानिक आदेश।

एतद्वारा, केंद्र सरकार भारत के दूतावास, हेलसिंकी में श्री ललित मोहन, सहायक अनुभाग अधिकारी को दिनांक 16 जून, 2022 से सहायक कौंसुलर अधिकारी के तौर पर कौंसुलर सेवाओं के निर्वहन के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. टी-4330/01/2022(23)]

एस.आर.एच. फहमी, उप सचिव (कांसुलर)

**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
(CPV Division)**

New Delhi, the 16th June, 2022

S.O. 586.—Statutory Order in pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby appoints Mr. Lalit Mohan, Assistant Section Officer as Assistant Consular Officer in the Embassy of India, Helsinki to perform the Consular services with effect from 16 June, 2022.

[F. No.T-4330/01/2022(23)]

S.R.H FAHMI, Dy. Secy. (Consular)

नई दिल्ली, 16 जून, 2022

का.आ. 587.—राजनयिक और कौंसुलीय अधिकारी (शपथ एवं फीस) के अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में वैधानिक आदेश।

एतद्वारा, केंद्र सरकार भारत के दूतावास, रियाद में प्रकाश कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी, को दिनांक 16 जून, 2022 से सहायक कौंसुलर अधिकारी के तौर पर कौंसुलर सेवाओं के निर्वहन के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. टी-4330/01/2022(24)]

एस.आर.एच. फहमी, उप सचिव (कांसुलर)

New Delhi, the 16th June, 2022

S.O. 587.—Statutory Order in pursuance of clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri Prakash Kumar, Assistant Section Officer in the Embassy of India, Riyadh as Assistant Consular Officer to perform Consular services with effect from June 16, 2022.

[F. No. T-4330/01/2022(24)]

S.R.H FAHMI, Dy. Secy. (Consular)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

का.आ. 588.— केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, गृह (पुलिस) अनुभाग-11, लखनऊ की अधिसूचना सं. 1691(1)/6-पी-11-2021-12(116)बी/2020, दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से जारी सम्मति से, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत श्री रामभावन, पुत्र स्वर्गीय चुन्ना प्रसाद, निवासी जवाहर नगर, नारायणी, जिला-बांदा, उत्तर प्रदेश, द्वारा एक अन्य व्यक्ति नामतः प्रकाश प्रधान, पुत्र श्री रमेश चंद्र प्रधान, निवासी ग्राम कन्नापुर, पत्रालय ओलीकोना, जिला पूरी, ओडिशा के साथ साठ-गांठ कर वर्ष 2015 से इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन शोषण संबंधी कृत्य में लिप्त बच्चों को चित्रित करने वाले सामग्री सहित अश्लील सामग्री के प्रकाशन/संचार करने के अनैतिक कृत्य में लिप्त होने के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 67-बी के अंतर्गत किए गए अभिकथित अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त उत्तर प्रदेश राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/15/2022-एवीडी-II]

संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 7th April, 2022

S.O. 588.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Uttar Pradesh, issued vide Notification No.1691(1)/6-P-11-2021-12(116)B/2020 dated 16 December, 2021, Home (Police) Section-11, Lucknow, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Uttar Pradesh for investigation into the offences(s) under section 67-B of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) alleged to have been committed by Shri Rambhawan S/o Late Chunna Prasad R/o Jawahar Nagar, Naraini, District Banda, Uttar Pradesh working as Junior Engineer in Irrigation Department of Government of Uttar Pradesh at Chitrakoot, Uttar Pradesh by indulging in immoral practices of publishing/ transmitting obscene material including the material depicting children in sexually explicit act in electronic form over the internet in connivance with another person namely Prakash Pradhan, S/o Shri Ramesh Chandra Pradhan, R/o Village Kannapur, Post Office Olikona, Distt. Puri, Odisha from the year 2015 onwards and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/15/2022-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

का.आ. 589.— केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, गृह (पुलिस) अनुभाग-11, लखनऊ की अधिसूचना सं. 1691(5)/6-पी-11-2021-12(116)बी/2020, दिनांक 16 दिसंबर, 2021 के माध्यम से जारी सम्मति से, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत श्री रामभावन, पुत्र स्वर्गीय चुन्ना प्रसाद, निवासी जवाहर नगर, नारायणी, जिला-बांदा, उत्तर प्रदेश, द्वारा किसी श्री सावकरे राजकुमार हेमकांत, निवासी जलगांव, महाराष्ट्र के साथ सांठ-गांठ कर वर्ष 2015-16 से इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन शोषण संबंधी कृत्य में लिप्त बच्चों को चित्रित करने वाले सामग्री सहित अश्लील सामग्री के प्रकाशन/संचार करने के अनैतिक कृत्य में लिप्त होने के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 67-बी के अंतर्गत किए गए अभिकथित अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त उत्तर प्रदेश राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/13/2022-एवीडी-II]

संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव

New Delhi, the 7th April, 2022

S.O. 589.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Uttar Pradesh, issued vide Notification No. 1691(5)/6-P-11-2021-12(116)B/2020 dated 16 December, 2021, Home (Police) Section-11, Lucknow, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Uttar Pradesh for investigation into the offences(s) under section 67-B of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) alleged to have been committed by Shri Rambhawan S/o Late Chunna Prasad R/o Jawahar Nagar, Naraini, District Banda, Uttar Pradesh working as Junior Engineer in Irrigation Department of Government of Uttar Pradesh at Chitrakoot, Uttar Pradesh by indulging in immoral practices of publishing/ transmitting obscene material including the material depicting children in sexually explicit act in electronic form over the internet in connivance with one Shri Sawkare Rajkumar Hemkant, R/o Jalgaon, Maharashtra from the year 2015-16 onwards and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/13/2022-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

का.आ. 590.—केन्द्र सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम संख्या 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्य सरकार, गृह, कारागार एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रांची की अधिसूचना सं. 10/सीबीआई.-414/2021-4804/रांची दिनांक 13.12.2021 के माध्यम से प्राप्त सहमति से श्री अभिजीत दास, जनरल मैनेजर (जी.एम)/एरिया मैनेजर (ई एण्ड एम), ईसीएल, मुगमा एरिया, धनबाद झारखण्ड, द्वारा कथित रूप से आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में आर्थिक संसाधनों या आय से अधिक संपत्ति के कब्जे में होने के संबंध में धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(ई) (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के संशोधन पूर्व) (1988 का 49) एवं वर्तमान अनुरूप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) (2018 के अधिनियम 16 द्वारा संशोधन) की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(बी) के तहत अपराध (अपराधों) का

अन्वेषण तथा ऐसे अपराध (अपराधों) से जुड़े या उससे सम्बद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त झारखण्ड राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/11/2022-एवीडी-II]

संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव

New Delhi, the 7th April, 2022

S.O. 590.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Jharkhand, issued vide Notification No. 10/C.B.I.-414/2021-4806/Ranchi dated 13.12.2021, Home, Prison and Disaster Management Department, Ranchi, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Jharkhand for investigation into the offences(s) under section 13(2) r/w section 13(1)(e) (before amendment to the Prevention of Corruption Act, 1988) (49 of 1988) and presently corresponding section 13(2) r/w section 13(1)(b) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) (as amended by Act 16 of 2018) alleged to have been committed by Shri Abhijit Das, General Manager (GM)/Area Manager (E&M), ECL, Mugma Area, Dhanbad (Jharkhand) pertaining to be in possession of pecuniary resources or property disproportionate to his known sources of income and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/11/2022-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

का.आ. 591.—केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, गृह (पुलिस) अनुभाग-11, लखनऊ की अधिसूचना सं. 1691(2)/6-पी-11-2021-12(116)बी/2020, दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से जारी सम्मति से, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत श्री रामभावन, पुत्र स्वर्गीय चुन्ना प्रसाद, निवासी जवाहर नगर, नारायणी, जिला-बांदा, उत्तर प्रदेश, द्वारा एक अन्य व्यक्ति नामतः श्री टी अजय, पुत्र तिरुमाला श्रीनिवासुलु, स्थायी निवासी 3-9-612/सी, प्लॉट सं. 77 ए, पद्मावती नगर, मंसूराबाद, हैदराबाद, तेलंगाना के साथ सांठ-गांठ कर वर्ष 2015-16 से इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन शोषण संबंधी कृत्य में लिप्त बच्चों को चित्रित करने वाले सामग्री सहित अश्लील सामग्री के प्रकाशन/संचार करने के अनैतिक कृत्य में लिप्त होने के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 67-बी के अंतर्गत किए गए अभिकथित अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त उत्तर प्रदेश राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/14/2022-एवीडी-II]

संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव

New Delhi, the 7th April, 2022

S.O. 591.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Uttar Pradesh, issued vide Notification No. 1691(2)/6-P-11-2021-12(116)B/2020 dated 16 December, 2021, Home (Police) Section-11, Lucknow, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Uttar Pradesh for investigation into the offences(s) under section 67-B of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) alleged to have been committed by Shri Rambhawan S/o Late Chunna Prasad R/o Jawahar Nagar, Naraini, District Banda, Uttar Pradesh working as Junior Engineer in Irrigation Department of Government of Uttar Pradesh at Chitrakoot, Uttar Pradesh by indulging in immoral practices of publishing/ transmitting obscene material including the material depicting children in sexually explicit act in

electronic form over the internet in connivance with another person namely Shri T Ajay, S/o Shri Tirumala Srinivasulu, permanent resident of 3-9-612/c, Plot No. 77a, Padmavathi Nagar, Mansoorabad, Hyderabad, Telengana from the year 2015-16 onwards and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/14/2022-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

का.आ. 592.—केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, गृह (पुलिस) अनुभाग-11, लखनऊ की अधिसूचना सं. 1691(6)/6-पी-11-2021-12(116)बी/2020, दिनांक 16 दिसंबर, 2021 के माध्यम से जारी सम्मति से, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत श्री रामभावन, पुत्र स्वर्गीय चुन्ना प्रसाद, निवासी जवाहर नगर, नारायणी, जिला-बांदा, उत्तर प्रदेश, द्वारा श्री विश्वनाथ शुक्ला, पुत्र आदित्य नारायण शुक्ला, निवासी 1033 छा, एस. पी. निवास के पीछे, सिविल लाईन, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के साथ साठ-गांठ कर वर्ष 2015-16 से इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन शोषण संबंधी कृत्य में लिप्त बच्चों को चित्रित करने वाले सामग्री सहित अश्लील सामग्री के प्रकाशन/संचार करने के अनैतिक कृत्य में लिप्त होने के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 67-बी के अंतर्गत किए गए अभिकथित अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त उत्तर प्रदेश राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/16/2022-एवीडी-II]

संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव

New Delhi, the 11th April, 2022

S.O. 592.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Uttar Pradesh, issued vide Notification No. 1691(6)/6-P-11-2021-12(116)B/2020 dated 16 December, 2021, Home (Police) Section-11, Lucknow, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Uttar Pradesh for investigation into the offence(s) under section 67-B of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) alleged to have been committed by Shri Rambhawan S/o Late Chunna Prasad R/o Jawahar Nagar, Naraini, District Banda, Uttar Pradesh working as Junior Engineer in Irrigation Department of Government of Uttar Pradesh at Chitrakoot, Uttar Pradesh by indulging in immoral practices of publishing/ transmitting obscene material including the material depicting children in sexually explicit act in electronic form over the internet in connivance with one Shri Vishwa Nath Shukla, S/o Aditya Narayan Shukla R/o 1033 chha, Behind S. P. Awas, Civil Line, Fatehpur, Uttar Pradesh from the year 2015-16 onwards and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/16/2022-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

का.आ. 593.—केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात राज्य सरकार, गृह विभाग, गुजरात की अधिसूचना सं. एसबी-IV/सीबीआई/102021/जीओआई/15, दिनांक 07.01.2022 के माध्यम से जारी सम्मति से, श्री महेश कुमार काशाभाई चौहान, पुत्र श्री काशाभाई, निवासी 11, नीतिनगर, गांधीवास टोलनाका के समीप, साबरमती, अहमदाबाद, इंस्टाग्राम अकाउंट अर्थात्, “pics_and_videos_sell”, इ-मेल-आईडी paralalu421@gmail.com और मोबाईल नं. +918849615926 के उपयोगकर्ता द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन शोषण संबंधी कृत्य या व्यवहार इत्यादि में लिप्त बच्चों को चित्रित करने वाले सामग्री के विज्ञापन/प्रकाशन/संचार के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 67-बी के अंतर्गत किए गए अभिकथित अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त गुजरात राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/17/2022-एवीडी-II]

संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव

New Delhi, the 11th April, 2022

S.O. 593.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Gujarat, issued vide Notification No. SB-IV/CBI/102021/GOI/15 dated 07.01.2022, Home Department, Gujarat, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Gujarat for investigation into the offence(s) under section 67-B of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) alleged to have been committed by Shri Mahesh Kumar Kashabhai Chauhan S/o Shri Kashabhai R/o 11, Nitinagar, Near Gandhivas Tolnaka, Sabarmati, Ahmedabad, user of Instagram account i.e. “pics_and_videos_sell”, email-id paralalu421@gmail.com and mobile number +918849615926 pertaining to advertisement/publishing/ transmitting of material depicting children engaged in sexually explicit act or conduct etc. in electronic form by using social media platform and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/17/2022-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

का.आ. 594.—केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, गृह (पुलिस) अनुभाग-11, लखनऊ की अधिसूचना सं. 1691(3)/6-पी-11-2021-12(116)बी/2020, दिनांक 16 दिसंबर, 2021 के माध्यम से जारी सम्मति से, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत श्री रामभावन, पुत्र स्वर्गीय चुन्ना प्रसाद, निवासी जवाहर नगर, नारायणी, जिला-बांदा, उत्तर प्रदेश, द्वारा किसी श्री अजीत कुमार, पुत्र श्री संजय कुमार, निवासी रायपुरा, फतवा फतुहा, जिला पटना, बिहार के साथ सांठ-गांठ कर वर्ष 2015-16 से आगे इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन शोषण संबंधी कृत्य में लिप्त बच्चों को चित्रित करने वाले सामग्री सहित अश्लील सामग्री के प्रकाशन/संचार करने के अनैतिक कृत्य में लिप्त होने के संबंध में सूचना

प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 67-बी के अंतर्गत किए गए अभिकथित अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त उत्तर प्रदेश राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/19/2022-एवीडी-II]

संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव

New Delhi, the 11th April, 2022

S.O. 594.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Uttar Pradesh, issued vide Notification No. 1691(3)/6-P-11-2021-12(116)B/2020 dated 16 December, 2021, Home (Police) Section-11, Lucknow, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Uttar Pradesh for investigation into the offence(s) under section 67-B of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) alleged to have been committed by Shri Rambhawan S/o Late Chunna Prasad R/o Jawahar Nagar, Naraini, District Banda, Uttar Pradesh working as Junior Engineer in Irrigation Department of Government of Uttar Pradesh at Chitrakoot, Uttar Pradesh by indulging in immoral practices of publishing/ transmitting obscene material including the material depicting children in sexually explicit act in electronic form over the internet in connivance with one Shri Ajit Kumar, S/o Sanjay Kumar, R/o Raipura, Fatwa Fatuha, District Patna, Bihar from the year 2015-16 onwards and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/19/2022-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

का.आ. 595.—केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, गृह (पुलिस) अनुभाग-11, लखनऊ की अधिसूचना सं. 1691(4)/6-पी-11-2021-12(116)बी/2020, दिनांक 16 दिसंबर, 2021 के माध्यम से जारी सम्मति से, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत श्री रामभावन, पुत्र स्वर्गीय चुन्ना प्रसाद, निवासी जवाहर नगर, नारायणी, जिला-बांदा, उत्तर प्रदेश, द्वारा किसी अनुराग मनोहर रावले, पुत्र मनोहर रावले निवासी 05, उन्नति नगर, पार्वती नगर, नागपुर, महाराष्ट्र के साथ सांठ-गांठ कर वर्ष 2015-16 से इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन शोषण संबंधी कृत्य में लिप्त बच्चों को चित्रित करने वाले सामग्री सहित अश्लील सामग्री के प्रकाशन/संचार करने के अनैतिक कृत्य में लिप्त होने के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 67-बी के अंतर्गत किए गए अभिकथित अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त उत्तर प्रदेश राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/12/2022-एवीडी-II]

संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव

New Delhi, the 11th April, 2022

S.O. 595.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Uttar Pradesh, issued vide Notification No. 1691(4)/6-P-11-2021-12(116)B/2020 dated 16 December, 2021, Home (Police) Section-11, Lucknow, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Uttar Pradesh for investigation into the offence(s) under section 67-B of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) alleged to have been committed by Shri Rambhawan S/o Late Chunna Prasad R/o Jawahar Nagar, Naraini, District Banda, Uttar Pradesh working as Junior Engineer in Irrigation Department of Government of Uttar Pradesh at Chitrakoot, Uttar Pradesh by indulging in immoral practices of publishing/transmitting obscene material including the material depicting children in sexually explicit act in electronic form over the internet in connivance with one Anurag Manohar Ravale, S/o Manohar Ravale R/o 05, Unnati Nagar, Parvati Nagar, Nagpur, Maharashtra from the year 2015-16 onwards and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/12/2022-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

का.आ. 596.—केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश राज्य सरकार, अधिसूचना सं. एफ 12-102/2021/बी-1/दो, दिनांक 29.12.2021, गृह विभाग, भोपाल, के माध्यम से जारी सहमति से नेमावर में दिनांक 13.05.2021 से 17.05.2021 की अवधि के दौरान 05 व्यक्तियों के व्यपहरण/अपहरण एवं हत्या की घटना से जुड़े अपराध (अपराधों) का भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 302, 363 [भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की संवर्धित धारा 364, 376, 376(2) (एन), 120बी, 201], यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (2012 का 32) की धारा 5 (एल) तथा 6, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 3(2)(v) और 3(2)(vए) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 66बी और 66सी के तहत थाना नेमावर, देवास (म.प्र.) में दर्ज अपराध सं. 132/2021 से संबंधित अपराध(धों) का अन्वेषण करने के लिए तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त मध्य प्रदेश राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/21/2022-एवीडी-II]

संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव

New Delhi, the 11th April, 2022

S.O. 596.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Madhya Pradesh, issued vide Notification No. F 12-102/2021/B-1/Two dated 29.12.2021 of Home Department, Bhopal, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Madhya Pradesh for investigation into the offence(s) relating to Crime No. 132/2021, registered at Police Station Nemawar, Dewas (M.P.), under section 363 of the Indian Penal Code (45 of 1860) [enhanced sections 302, 364, 376, 376(2)(n), 201, 120B of the Indian Penal Code (45 of 1860)], section 5(l) and 6 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012), section 3(2)(v) and 3(2)(va) of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989) and section 66B and 66C of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) pertaining to the incident of Kidnapping/abduction and murder of 05 persons, occurred during the period from 13.05.2021 to 17.05.2021 at Nemawar and any attempt, abetment and/or

conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/21/2022-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2022

का.आ. 597.—केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार, गृह विभाग, मुंबई के आदेश सं. सीबीआई 2020/सीआर 456/पीओएल-2, दिनांक 24 जनवरी, 2022 के माध्यम से जारी सम्मति से, आईएफसीआई लि. को लगभग रु. 22,06,20,106/- की सदोष हानि पहुँचाने के लिए (1) मेसर्स गीतांजलि जेम्स लि., (2) श्री मेहुल चिन्नुभाई चोकसी (संप्रवर्तक और निजी गारंटीकर्ता), (3) मेसर्स सूरजमल लल्लूभाई & कं. (मूल्यकार), (4) श्री नरेंद्र झावेरी (मूल्यकार), (5) श्री प्रदीप सी. शाह (मूल्यकार) और (6) श्री श्रेणिक शाह (मूल्यकार), अज्ञात लोक सेवकों और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 120बी, 420, 468 और 471 तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 (1988 का 49) (जैसा कि दिनांक 26.07.2018 को संशोधन किए जाने के पूर्व विहित था) की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(डी) के अंतर्गत किए गए दण्डनीय अपराध(धों) के संबंध में दिनांक 24.11.2020 को सहायक महाप्रबंधक (विधि), आईएफसीआई लि., नरीमन प्वाइंट, मुंबई द्वारा की गई शिकायत से उत्पन्न अपराध(धों) का अन्वेषण करने तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त महाराष्ट्र राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/23/2022-एवीडी-II]

संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव

New Delhi, the 18th April, 2022

S.O. 597.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government Maharashtra, issued vide Order No. CBI 2020/CR 456/POL-2 dated 24 January, 2021 of Home Department, Mumbai, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Maharashtra for investigation into the offence(s) arising out of the complaint dated 24.11.2020 lodged by Assistant General Manager (Law), IFCI Ltd., Nariman Point, Mumbai against (1) M/s Gitanjali Gems Ltd., (2) Sh. Mehul Chinubhai Choksi (Promotor and Personal Guarantor), (3) M/s Surajmal Lallubhai & Co. (Valuer), (4) Sh. Narendra Jhaveri (Valuer), (5) Sh. Pradip C. Shah (Valuer) and (6) Sh. Shrenik Shah (Valuer), unknown public servants and other persons for causing wrongful loss of approx. Rs. 22,06,20,106/- to the IFCI Ltd. punishable under section 120B, 420, 468 and 471 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and section 13(2) r/w section 13(1)(d) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) (as stood before amendments made w.e.f. 26.07.2018) and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/23/2022-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2022

का. आ. 598.— केंद्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, RC0042020A0003 के संबंध में निम्नलिखित अपराध निम्नलिखित अधिनियम जिनके अधीन हुए किसी अपराध जिनकी जाँच दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों द्वारा की जानी है, को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

- (1) जम्मू एवं कश्मीर वन अधिनियम, 1987 (1987 का राज्य अधिनियम II);
- (2) जम्मू एवं कश्मीर विद्युत अधिनियम, 1997 (1997 का राज्य अधिनियम XIV);
- (3) जम्मू एवं कश्मीर विद्युत अधिनियम, 2010 (2010 का राज्य अधिनियम XIII);
- (4) जम्मू एवं कश्मीर निर्माण कार्य नियंत्रण अधिनियम, 1988 (1988 का राज्य अधिनियम XV);
- (5) जम्मू एवं कश्मीर पर्यटक व्यापार पंजीकरण अधिनियम, 1978 (1978 का राज्य अधिनियम IX);
- (6) जम्मू एवं कश्मीर जलापूर्ति अधिनियम, 1963 (1963 का राज्य अधिनियम XXI);
- (7) जम्मू एवं कश्मीर जल संसाधन (विनियमन & प्रबंधन) अधिनियम, 2010 (2010 का राज्य अधिनियम XXI);
- (8) जम्मू एवं कश्मीर भू-राजस्व अधिनियम, 1996 (1996 का राज्य अधिनियम XII);

और उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम के संबंधित या ससंग में किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और षड्यंत्र या उसी संव्यवहार के दौरान या उन्हीं तथ्यों या दोनों से उत्पन्न कोई अन्य अपराध।

[फा. सं. 228/68/2021-एवीडी-II]

संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव

New Delhi, the 21st April, 2022

S.O. 598.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government hereby specifies the following Acts under which any offences committed shall be investigated by the Delhi Special Police Establishment, in connection with RC0042020A0003, namely :-

- (1) the Jammu and Kashmir Forest Act, 1987 (State Act II of 1987);
- (2) the Jammu and Kashmir Electricity Act, 1997 (State Act XIV of 1997);
- (3) the Jammu and Kashmir Electricity Act, 2010 (State Act XIII of 2010);
- (4) the Jammu and Kashmir Control of Building Operations Act, 1988 (State Act XV of 1988);
- (5) the Jammu and Kashmir Registration of Tourist Trade Act, 1978 (State Act IX of 1978);
- (6) the Jammu and Kashmir Water Supply Act, 1963 (State Act XXI of 1963);
- (7) the Jammu and Kashmir Water Resources (Regulation & Management) Act, 2010 (State Act XXI of 2010);
- (8) the Jammu and Kashmir Land Revenue Act, 1996 (State Act XII of 1996)

and any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with above mentioned acts or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts or both.

[F. No. 228/68/2021-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2022

का.आ. 599.—केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार के गृह विभाग (पुलिस शाखा), पटना की अधिसूचना सं. 9/सी.बी.आई.-80-07/2021 एचपी-1484, दिनांक 18.02.2022 के माध्यम से जारी सम्मति से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, कस्तुरी सराय शाखा के संबंध में पातेपुर पुलिस थाना, जिला वैशाली, बिहार में भारतीय दंड संहिता (1869 का 45) की धारा 420, 408, 409, 467, 468, 469, 470 और 120बी के तहत दिनांक 06.09.2021 को दर्ज मामला अपराध सं. 187/2021 से जुड़े अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त बिहार राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/29/2022-एवीडी-II]

संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव

New Delhi, the 13th May, 2022

S.O. 599.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Bihar, issued vide Notification No. 9/C.B.I.-80-07/2021 HP-1484 dated 18.02.2022, Home Department (Police Branch), Patna hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Bihar for investigation into the offence(s) relating to Case Crime No. 187/2021 dated 06.09.2021, registered under sections 420, 408, 409, 467, 468, 469, 470 and 120B of the Indian Penal Code (45 of 1860) at Police Station Patepur, District-Vaishali, Bihar, in respect of Uttar Bihar Gramin Bank, Kasturi Sarai Branch and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/29/2022-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 मई, 2022

का.आ. 600.—केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार, गृह विभाग, मुंबई के आदेश सं. सीबीआई 2021/सीआर 170/पीओएल-2, दिनांक 26.03.2021 के माध्यम से जारी सम्मति से, श्री प्रशांत पांडुरंग चुयेकर, निवासी चुये, टाल कारवीर, जिला कोल्हापुर द्वारा दिनांक 24.03.2021 को शिकायतकर्ता के सब्सिडी राशि के परिनिर्धारण करने के लिए अनुचित लाभ की माँग करने के लिए श्री नीरज कुमार व अन्य अज्ञात निजी व्यक्तियों/सरकारी सेवकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 (1988 का 49) (2018 में यथा संशोधित) की धारा 7 के अंतर्गत दर्ज कराई गई शिकायत से उत्पन्न अपराध(धों) का अन्वेषण करने तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त महाराष्ट्र राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/03/2022-एवीडी-II]

जी. के. सिन्हा, अवर सचिव

New Delhi, the 24th May, 2022

S.O. 600.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Maharashtra, issued vide Order No. CBI 2021/CR 170/POL-2 dated 26.03.2021, Home Department, Mumbai, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Maharashtra for investigation into the offence(s) under section 120-B of the Indian Penal Code (45 of 1860) and section 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) (as amended in 2018), arising out of the complaint dated 24.03.2021 lodged by Shri Prashant Pandurang Chuyekar, R/o Chuye, Tal Karveer, District Kolhapur against Shri Neeraj Kumar and other unknown private persons/public servants pertaining to demand of undue advantage for settlement of the subsidy amount of the complainant and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/03/2022-AVD-II]

G.K SINHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 जून, 2022

का.आ. 601.—केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उपधारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार, गृह विभाग, मुंबई के आदेश सं. सीबीआई 2021/सीआर 78/पोल-2, दिनांक 04 मार्च, 2022 के माध्यम से जारी सम्मति से, मेसर्स उशदेव इंटरनेशनल लिमिटेड, मुंबई, इसके निदेशकों/गारंटर्स श्रीमती सुमन गुप्ता और श्री प्रतीक गुप्ता, अज्ञात लोक सेवकों व अन्य के विरुद्ध भारतीय स्टेट बैंक और चार अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों नामतः सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (अब पंजाब नेशनल बैंक) और इंडियन ओवर्सीज़ बैंक को लगभग 1438.45 करोड़ रुपए की सदोष हानि पहुँचाने के लिए दिनांक 09.12.2020 को श्री सनातन मिश्रा, उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, दाबयुक्त आस्तियाँ प्रबंधन शाखा-II, नरीमन प्वाइंट, मुंबई द्वारा भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 120बी सपठित धारा 420, 477-ए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में दिनांक 26.07.2018 को किए गए संशोधन से पूर्व जैसा विहित था) की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में दर्ज कराई गई शिकायत से उत्पन्न अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त महाराष्ट्र राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/34/2022-एवीडी-II]

संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव

New Delhi, the 8th June, 2022

S.O. 601.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Maharashtra, issued vide Order No. CBI 2021/CR 78/POL-2 dated 04th March, 2022 of Home Department, Mumbai, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Maharashtra for investigation into the offence(s) arising out of the complaint dated 09.12.2020 lodged by Sh. Sanatan Mishra, Deputy General Manager, State Bank of India, Stressed Assets Management Branch-II, Nariman Point, Mumbai against M/s Ushdev International Ltd., Mumbai, its Directors/Guarantors Mrs. Suman Gupta and Sh. Prateek Gupta, unknown public servants and others for causing wrongful loss of approx. Rs. 1438.45 crores to the State Bank of India and four other public sector Banks namely Central Bank of India, Bank of Maharashtra, Oriental Bank of Commerce (now Punjab National Bank) and Indian Overseas Bank, punishable under section 120B r/w 420, 477-A of the Indian Penal Code (45 of 1860) and section 13(2) r/w section 13(1)(d) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) (as stood before the amendment made to the Prevention of Corruption Act, 1988 w.e.f. 26.07.2018) and any attempt, abetment and/or conspiracy, in

relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/34/2022-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 जून, 2022

का.आ. 602.—केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उपधारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार, गृह विभाग, मुंबई के आदेश सं. सीबीआई 2021/सीआर 222/पोल-2, दिनांक 23.03.2022 के माध्यम से जारी सम्मति से, श्री राणा कपूर, तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यस बैंक लिमिटेड, यस बैंक के अज्ञात अधिकारियों, मेसर्स रिलायंस कॉमर्शियल फायनांस लिमिटेड, मेसर्स रिलायंस कॉमर्शियल फायनांस लिमिटेड के अज्ञात अधिकारियों व अन्य के विरुद्ध यस बैंक लिमिटेड को लगभग 1984 करोड़ रुपए की सदोष हानि पहुँचाने के लिए दिनांक 24.11.2020 को श्री आशीष विनोद जोशी, मुख्य सतर्कता अधिकारी, यस बैंक लिमिटेड, मुंबई द्वारा भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 120बी सपठित धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में दिनांक 26.07.2018 को किए गए संशोधन से पूर्व जैसा विहित था) की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में दर्ज कराई गई शिकायत से उत्पन्न अपराध(धों) का अन्वेषण तथा उसके मूल अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त महाराष्ट्र राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/42/2022-एवीडी-II]

संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव

New Delhi, the 8th June, 2022

S.O. 602.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Maharashtra issued vide Order No. CBI 2021/CR 222/POL-2 dated 23.03.2022, Home Department, Mumbai, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Maharashtra for investigation into the offence(s) arising out of the complaint dated 24.11.2020 lodged by Shri Ashish Vinod Joshi, Chief Vigilance Officer, Yes Bank Ltd., Mumbai against Shri Rana Kapoor, the then MD and CEO of Yes Bank Ltd., unknown officials of Yes Bank, M/s Reliance Commercial Finance Limited, unknown officials of M/s Reliance Commercial Finance Limited and others for causing wrongful loss of approx. Rs. 1984 crores to the Yes Bank Ltd., punishable under section 120B r/w section 420 of Indian Penal Code (45 of 1860) and section 13(2) r/w section 13(1)(d) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) (as stood before the amendment made to the Prevention of Corruption Act, 1988 w.e.f. 26.07.2018), substantive offences thereof and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/42/2022-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जून, 2022

का.आ. 603.—केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार, गृह विभाग, मुंबई के आदेश सं. 2021/सीआर 221/पोल-2, दिनांक 04.03.2022 के माध्यम से जारी सहमति से, श्री राणा कपूर, तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यस बैंक लिमिटेड, यस बैंक लिमिटेड के अज्ञात अधिकारियों, मेसर्स रिलायंस होम फायनांस लिमिटेड, मेसर्स रिलायंस होम फायनांस लिमिटेड के अज्ञात अधिकारियों व अन्य के विरुद्ध यस बैंक लिमिटेड को लगभग 1353.50 करोड़ रुपए की सदोष हानि पहुँचाने के लिए दिनांक 24.11.2020 को श्री आशीष विनोद जोशी, मुख्य सतर्कता अधिकारी, यस बैंक लिमिटेड, मुंबई द्वारा भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 120बी सपठित धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में दिनांक 26.07.2018 को किए गए संशोधन से पूर्व जैसा विहित था) की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में दर्ज कराई गई शिकायत से उत्पन्न अपराध(धों) का अन्वेषण तथा उसके मूल अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त महाराष्ट्र राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/43/2022-एवीडी-II]

संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव

New Delhi, the 9th June, 2022

S.O. 603.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Maharashtra issued vide Order No. CBI 2021/C.R. 221/Pol-2 dated 04.03.2022, Home Department, Mumbai, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Maharashtra for investigation into the offence(s) arising out of the complaint dated 24.11.2020 lodged by Shri Ashish Vinod Joshi, Chief Vigilance Officer, Yes Bank Ltd., Mumbai against Shri Rana Kapoor, the then MD and CEO of Yes Bank Ltd., unknown officials of Yes Bank, M/s Reliance Home Finance Limited, unknown officials of M/s Reliance Home Finance Limited and others for causing wrongful loss of approx. Rs. 1353.50 crores to the Yes Bank Ltd., punishable under section 120B r/w section 420 of Indian Penal Code (45 of 1860) and section 13(2) r/w section 13(1)(d) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) (as stood before the amendment made to the Prevention of Corruption Act, 1988 w.e.f. 26.07.2018), substantive offences thereof and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/43/2022-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जून, 2022

का.आ. 604.—केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उपधारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार, गृह विभाग, मुंबई के आदेश सं. सीबीआई 2021/सीआर 346/पोल-2, दिनांक 17 जनवरी, 2022 के माध्यम से जारी सम्मति से, (1) श्री संभाजी चवन (आईटीएस:2008), तत्कालीन संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी), मुंबई (2) श्री प्रकाश एस. काम्बले (आईटीएस:2013), उप डीजीएफटी, मुंबई (3) श्री अभिषेक अनिल कुमार अगरवाल, संयुक्त

प्रबंध निदेशक, मेसर्स राधा माधव कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दमन (4) श्री नितिन नांबियार, चार्टर्ड अकाउंटेंट और (5) श्री रमेश चवन, डीजीएफटी परामर्शदाता तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 120बी सपठित धारा 420, 467, 468 और 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धाराएँ 7, 7ए, 8, 9, 10 और 12 के तहत किए गए अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त महाराष्ट्र राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/32/2022-एवीडी-II]

संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव

New Delhi, the 9th June, 2022

S.O. 604.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Maharashtra, issued vide Order No. CBI 2021/CR 346/POL-2 dated 17th January, 2022 of Home Department, Mumbai, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Maharashtra for investigation into the offence(s) under section 120B r/w 420, 467, 468 and 471 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and sections 7, 7A, 8, 9, 10 and 12 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) against (1) Shri Sambhaji Chavan (ITS:2008), the then Joint Director General of Foreign Trade (DGFT), Mumbai (2) Sh. Prakash S. Kamble (ITS:2013), Dy. DGFT, Mumbai (3) Sh. Abhishek Anil Kumar Agarwal, Joint Managing Director of M/s Radha Madhav Corporation Limited, Daman (4) Sh. Nitin Nambiar, Chartered Accountant and (5) Sh. Ramesh Chavan, DGFT Consultant and other unknown persons and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/32/2022-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जून, 2022

का.आ. 605.— केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफ.19(18) गृह-5/2022, दिनांक 23.02.2022, गृह (ग्रेड-V) विभाग, जयपुर के माध्यम से जारी सहमति से (1) श्री सुशील कुमार कुमावत, मावली उप डाकघर के तत्कालीन उप डाकपाल (2) श्री रत्न लाल गवारिया, तत्कालीन शाखा डाकपाल, गड़ोली (3) श्री राधेश्याम पारिक, तत्कालीन ग्रामीण डाक सेवक, उप डाकघर मावली (4) श्री किशन लाल मेघवाल, तत्कालीन शाखा डाकपाल, भिमल तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, बहुमूल्य प्रतिभूति की जालसाज़ी, धोखाधड़ी के उद्देश्य के लिए जालसाज़ी, जालसाज़ी युक्त दस्तावेज़ को वास्तविक के रूप में उपयोग करने, खातों के फर्जीवाड़े, लोकसेवक द्वारा आपराधिक कदाचार तथा भारत सरकार को सदोष हानि कारित करने के संबंध में डाकघर के वरिष्ठ अधीक्षक, उदयपुर प्रभाग, उदयपुर, राजस्थान द्वारा दर्ज कराई गई दिनांक 17.01.2022 की शिकायत से उत्पन्न भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 तथा 477ए तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) (2018 के अधिनियम 16 द्वारा संशोधित) की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(ए) के तहत अपराध(धों) का अन्वेषण करने के लिए तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य

अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त राजस्थान राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/37/2022-एवीडी-II]

संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव

New Delhi, the 9th June, 2022

S.O. 605.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Rajasthan, issued vide Notification No. F.19(18)Home-5/2022 dated 23.02.2022 of Home (Gr.-V) Department, Jaipur, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Rajasthan for investigation into the offence(s) arising out of the complaint dated 17.01.2022 lodged by Senior Superintendent of Post Offices, Udaipur Division, Udaipur, Rajasthan against (1) Shri Sushil Kumar Kumawat, the then Sub Post Master of Mavli Sub Post Office (2) Shri Ratan Lal Gawariya, the then Branch Post Master, Gadoli (3) Shri Radheshyam Parik, the then Gramin Dak Sewak, Sub Post Office Mavli (4) Shri Kishan Lal Meghwal, the then Branch Post Master, Bhimal and others, pertaining to criminal conspiracy, cheating, forgery of valuable security, forgery for the purpose of cheating, using as genuine a forged document, falsification of accounts, criminal misconduct by public servant and causing wrongful loss to Government of India, punishable under sections 120B, 420, 467, 468, 471 and 477A of the Indian Penal Code (45 of 1860) and section 13(2) r/w section 13(1)(a) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) (as amended by the Act 16 of 2018) and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/37/2022-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 जून, 2022

का.आ. 606.—केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य सरकार, की अधिसूचना सं. एफ.19(54)गृह-5/2021, दिनांक 13.01.2022 गृह (गृ-V) विभाग, जयपुर के माध्यम से जारी सम्मति से, श्री विक्रम सिंह मीना, पुत्र श्री हेमराज मीना, तत्कालीन गुणवत्ता निरीक्षक, एफसीआई, बहरौंडा मंडी, सवाई माधोपुर, एफसीआई के अज्ञात लोक सेवकों व अन्य व्यक्तियों द्वारा भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धाराएँ 120बी और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) (2018 के अधिनियम 16 द्वारा यथासंशोधित) की धारा 7 के तहत किए गए अभिकथित अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त राजस्थान राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/24/2022-एवीडी-II]

संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव

New Delhi, the 10th June, 2022

S.O. 606.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Rajasthan, issued vide Notification No. F.19(54)Home-5/2021 dated 13.01.2022, Home (Gr.-V) Department, Jaipur, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Rajasthan for investigation into the offence(s) under sections 120B and 420 of the Indian Penal Code 1860 (45 of 1860) and under section 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) (as amended by Act 16 of 2018) alleged to have been committed by Shri Vikram Singh Meena, S/o Shri Hemraj Meena, the then Quality Inspector, FCI, Bahraunda Mandi, Sawai Madhopur, unknown public servants of FCI and other persons and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/24/2022-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जून, 2022

का.आ. 607.—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई शर्त सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1326 तारीख 11 जुलाई 2019, जो शर्त के राजपत्र क्रमांक 30, ता. 27 जुलाई 2019 और, का.आ. 9 ता. 05 जनवरी 2021, जो शर्त के राजपत्र क्रमांक 01, ता. 09 जनवरी 2021 में प्रकाशित की गई थी उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में हाइड्रोकार्बन के परिवहन के लिए मुन्द्रा भटिंडा विस्तृतिकरण पाइपलाइन त्रगडी से गुंदाला तक के मार्ग में अंच. पी. सी. अेल. — मित्तल पाइपलाइन्स लिमिटेड, मुन्द्रा जिल्ला कच्छ गुजरात राज्य द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी :

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियों जनता को तारीख 5 अक्टूबर, 2019 और 15 जून 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम अधिकारी द्वारा पाइपलाइन बिछाने के विरुद्ध जनता से प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद स्वीकार किया और निरस्त कर दिया ;

और सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के आधिन केन्द्रीय सरकार को रीपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रीपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि हाइड्रोकार्बन के परिवहन के लिए मुन्द्रा भटिंडा विस्तृतिकरण पाइपलाइन त्रगडी से गुंदाला तक के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का निश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि हाइड्रोकार्बन के परिवहन मुन्द्रा भटिंडा विस्तृतिकरण पाइपलाइन के लिए उपयोग का अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है के उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार, ईस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय, सभी विल्लगमों से मुक्त हो कर अंच. पी. सी. अेल. — मित्तल पाइपलाइन्स लिमिटेड, मुन्द्रा जिल्ला कच्छ गुजरात राज्य में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए अंच. पी. सी. अेल. — मित्तल पाइपलाइन्स लिमिटेड, मुन्द्रा जिल्ला कच्छ गुजरात राज्य, पूर्णतया उत्तरदाई होगी और पाइपलाइन से संबंधित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

जिला : कच्छ

राज्य : गुजरात

अनु. नं.	गाँव का नाम	तहसील	सर्वे / ब्लोक / सं (प्लोट सं.)	सब-डीव-सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6		
1	त्रगडी	मांडवी	Govt		56	12	04
			Govt-237		02	79	85
			238		00	56	03
			239		00	82	58
			240		00	80	10
			241		00	32	54
			257		00	00	20
			258		00	07	20
			259		00	52	14
			Govt-260		01	28	43
			265		00	49	31
			270		00	02	30
			Govt-260		00	19	05
			261		00	00	20
			266		00	20	35
			Govt-260		00	11	89
			267		00	00	48
			219		00	72	24
			220		00	35	50
			218		00	47	14
			Govt-226		00	60	81
			201		00	57	04
			Govt-226		00	67	19
			200		00	34	72
			Govt-226		00	26	85
			Govt-197		00	00	20
2	नाना भाडीया	मांडवी	River		00	52	29
			305	1	00	03	58
			Govt-553	P	00	53	72
			303		01	06	54
			304		00	03	68
			Govt-553	P1	10	65	25
			122		00	60	52
			121		00	75	52
3	कांडागरा मोटा	मुंद्रा	Govt-379		00	01	99
			Road		00	07	55
			380		00	63	92
			385		00	50	00
			387		00	43	00
			388		00	10	89
			390	2	00	55	80
			390	1	00	33	10
			396		00	52	72
			395		00	09	36

	कांडागरा मोटा चालु	मुंद्रा	394		00	64	18
			393	1	00	04	81
			402	1	00	10	21
			393	3	00	53	97
			Road		00	07	44
			Govt-517	P	01	47	99
			489	3	00	06	22
			489	2	00	00	20
			Road		00	11	46
			Govt-517	P	00	09	17
			506		00	49	19
			507		00	38	11
			484	4	00	07	55
			484	3	00	00	20
			508	2	00	02	93
			508	1	00	27	56
			Govt-483	4	00	02	00
			483	3	00	15	51
			483	1	00	00	20
			483	2	00	02	82
			509		00	00	20
			482	3	00	13	69
			Govt-482	4	00	02	02
			Govt-482	2	00	00	20
			482	1	00	23	00
			Road		00	07	35
			27		00	11	92
			29	3	00	18	31
			26		00	01	06
			29	1	00	01	36
			29	2	00	11	53
			30	2	00	12	52
			29	1	00	34	40
			45		00	10	82
			32		00	51	22
			Govt-33	3	00	56	29
			33	1	00	37	16
			33	2	00	12	65
			River		00	38	63
			122	2	00	41	46
			Road		00	06	67
			121		00	47	47
			120		00	95	33
			Govt-517	P	00	49	24
			150	2	00	31	31
			150	1	00	09	63
			149		00	62	80
			Road		00	08	29
			148		00	65	09

	कांडागरा मोटा चालु	मुद्रा	146		00	06	38
			147		00	85	69
			Govt-517	P	03	13	28
			159		00	37	92
4	खाखर मोटी	मुद्रा	213		00	35	04
			228		00	97	51
			227		00	61	12
			226		00	21	36
			Canal-233		00	20	50
			234		00	09	42
			235		00	13	37
			224		00	31	44
			223		00	35	73
			239		00	00	29
			CT		00	08	73
			222		00	52	45
			221		00	15	61
			241		00	39	93
			CT-528		00	15	36
			105		01	39	38
			107		00	58	56
			106		00	32	34
			G Panchayat-99		00	01	81
			G Panchayat-97		00	70	22
			96		00	05	18
			98		00	19	98
			Gauchar-48		00	30	33
			88		00	24	70
			87		00	48	29
			86		00	45	49
			54		00	00	20
			50		00	50	91
			51		00	57	03
			CT-526		00	05	06
			53		00	06	40
			52		00	60	81
			41		00	41	35
			44		00	00	20
			43		00	16	95
			42		00	38	97
			32		00	59	08
			35		00	02	74
			34		00	49	02
			N.H.Road-520		00	20	38
			33		00	49	62
			460		00	63	19
			461		00	08	58
			459		00	39	50
			458		00	57	32

			456		00	55	37
			463		00	00	20
			Govt-455		00	54	39
5	देशलपर	मुंद्रा	405		00	60	33
			Govt-570	P	00	08	03
			430	1	01	09	97
			430	2	01	00	80
			423		00	68	40
			424		00	31	68
			429		00	54	44
			428		00	44	93
			Govt-570	P	02	02	06
			13		00	69	52
			C.T		00	04	55
			18		00	00	20
			14		00	51	95
			15	1	00	49	28
			15	2	00	33	91
			Govt-570	P	02	37	93
			51	2	00	00	20
			52	2	00	00	20
			55		00	03	90
			Govt-570	P	00	02	99
			Govt-97	-	01	08	99
			99	-	00	41	92
			Govt-570	P	00	25	57
			100		00	89	50
			C.T.		00	06	88
			132		00	41	93
			131		00	52	81
			121		00	54	49
			122		00	34	19
			123		00	28	57
			124		00	68	26
			C.T.		00	05	18
			River		01	44	29
6	गेलडा	मुंद्रा	382		00	53	94
			Govt-383		00	10	90
			Govt-384		00	26	69
			C.T-412		00	04	44
			Govt-387		00	08	51
			389		00	28	45
			388		00	19	69
			Gauchar-378		01	61	01
			379		00	00	20
			Govt-376		00	18	62
			375		00	42	63
			Road -410		00	08	78
			309		00	03	29

			350		00	66	85
			349		01	10	43
			311		00	55	75
			312		00	42	76
			347		00	02	76
			313		00	77	05
			Govt -314		00	69	38
			317		00	21	34
			316		00	97	53
			315		00	28	25
			Govt-321		00	59	60
			Nala-414		00	16	26
			322		01	05	08
			323		00	86	92
			242		00	07	58
7	मुजपुर मोटी	मुद्रा	423		01	01	97
			424		00	20	37
			713	47	00	77	04
			713	18	00	47	26
			713	16	00	09	32
			Gauchar-727		00	10	72
8	प्रतापपर - 2	मुद्रा	Govt-1	P	03	43	02
			1	6	00	82	37
			1	8	00	79	76
			Govt-1	P	00	21	74
9	प्रागपर - 2	मुद्रा	65	2	00	38	25
			Nala		00	11	05
			65	1	00	19	30
			Nala		00	23	45
			Govt-65	P	01	67	46
			32		01	43	02
			Govt-65	P	02	28	92
			Govt		03	66	96
10	बराया	मुद्रा	24		00	42	62
			23		00	42	95
			Gauchar -22		01	52	68
			17		00	17	29
			Road-506		00	12	33
			14		00	37	74
			13		00	11	36
			Road-504		00	12	46
			Gauchar-141		00	42	91
			River-513		00	84	13
			156		00	03	10
			Canal-509		00	13	20
			Gauahar-160		01	46	17
			Road-502		00	08	66
			Road/Gauchar-231		00	07	41
			238		00	37	54

	बराया	मुंद्रा	237	00	49	21
			Road-489	00	07	05
			244	00	78	30
			246	00	43	32
			247	00	27	96
			248	00	00	61
			330	00	00	44
			328	00	05	09
			Road-491	00	11	90
			327	00	09	03
			326	00	11	01
			325	00	30	66
			324	00	21	48
			323	00	21	42
			322	00	21	54
			317	00	00	76
			321	00	04	01
			320	00	01	46
			Govt-318	00	46	87
			319	00	33	76
			Road-492	00	10	42
			Govt-277	00	00	27
			276	00	34	12
			278	00	16	44
			280	00	40	79
			Govt-281	00	63	49
			284	00	78	41
			285	00	60	24
			286	00	38	55
			287	00	56	36
			288	00	04	20
			293	00	32	66
			289	00	01	31
			292	00	85	63
			291	00	32	56
11	प्रागपर - 1	मुंद्रा	218	00	41	78
			219	00	54	50
			229	00	46	66
			232	00	20	69
			230	00	00	20
			231	01	04	57
12	टोडा	मुंद्रा	River-44	00	76	61
			Govt- 6	01	13	41
13	विरानीया	मुंद्रा	Gauchar-352	00	24	05
			Road-419	00	07	35
			Gauchar-351	00	67	44
			349	00	06	16
			Govt-348	00	02	17
			345	00	01	27

	विरानीया	मुंद्रा	346		00	44	40
			344		00	26	23
			343		00	22	00
14	भोरावा	मुंद्रा	293		00	00	26
			290		00	64	39
			292		00	00	20
			291		00	00	20
			289		00	33	31
			C.T-317		00	11	68
			282		00	00	20
			283		00	11	08
			288		00	23	53
			287		00	30	09
			286		00	03	99
			C.T-317		00	02	89
			318		00	45	90
			319		00	32	83
			320		00	38	94
			321		00	13	93
			356		00	93	25
			357		00	00	20
			355		00	25	76
			354		00	25	45
			353		00	52	90
			352		00	46	73
			349		00	45	95
			348		00	61	75
			346		00	00	20
			347		01	22	09
			344		00	09	30
15	गुंदाला	मुंद्रा	528		00	81	40
			529	1	00	56	68
			530		00	59	07
			531		00	26	71
			542		00	03	29
			544		00	61	84
			543	2	00	46	66
			C.T.		00	14	40
			550	2	00	19	73
			551		00	25	25
			550	1	00	06	47
			N.H.Road-550	1P1	00	25	11
			550	1	00	25	42
			552		00	15	57
			549		01	03	45
			554		00	04	11
			Canal	-	00	07	44
			Canal-562	P2P2	00	01	52
			Canal-561	P1P2	00	17	67

	गुंदाला	मुंद्रा	561		00	35	53
			C.T.		00	04	09
			555	1	00	71	52
			Road-555	1	00	07	89
			555	1	00	20	04
			555	2	00	04	18
			C.T.		00	06	43
			4	1	00	35	15
			4	2	00	14	96
			5		00	47	25
			6		00	55	51
			7		00	44	05
			Road-7		00	12	86
			7		00	08	74
			Govt-585	P	00	63	36
			94	2	00	15	82
			97		00	28	01
			C.T.		00	08	67
			133		00	61	81
			132		00	70	18
			Road		00	16	51
			138		01	26	68
			Govt-585	P	00	07	89
			201		00	24	29
			200		01	18	69
			199		00	58	23
			198	1	00	18	27
			198	2	00	15	96
			Govt-585	P	00	63	51
			198	3	00	03	26
			194		00	30	22
			193		00	15	21
			210	2	00	43	53
			210	1	00	17	08
			Govt-585	P	00	88	11

[फा. सं. आर-12031 / 2 / 2018-ओआर-1 / ई-26406]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 20th June, 2022

S.O. 607.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 1326, dated 11th July, 2019 and S.O. No 9 dated 5th January 2021, issued under subsection (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), Published in the Gazette of India No. 30 dated 27th July 2019, and No. 01 dated 9th January 2021. The Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to the notification for the purpose of the transportation of Hydrocarbon through Mundra - Bhatinda extension pipeline from village Tragadi, Taluka Mandvi, District Kutch to Gundala route taluka Mundra, District Kutch, State Gujarat through HPCL Mittal Pipelines Limited, Mundra, District Kutch of Gujarat state.

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 5th Oct, 2019 & 15th June, 2021;

And whereas, the objections received from the public to the pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority,

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted his report to the Central Government;

And where as the central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for the purpose of transportation of Hydrocarbon through Mundra-Bhatinda extension pipeline from village Tragadi, Taluka Mandvi, District Kutch to Gundala taluka Mundra, District Kutch, State Gujarat has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the rights of user in land specified in the Schedule appended to this notification is hereby required for the purpose of transportation of Hydrocarbon through Mundra - Bhatinda extension pipeline;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land required for the purpose of transportation of Hydrocarbon through Mundra - Bhatinda extension pipeline from village Tragadi, Taluka Mandvi, District Kutch to Gundala taluka Mundra, District Kutch, State Gujarat, pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in the HPCL Mittal Pipeline Limited, Mundra, District Kutch of Gujarat state, free from all encumbrances.

HPCL Mittal Pipelines Limited, Mundra, District Kutch of Gujarat state shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

DISTRICT : KUTCH

STATE : GUJARAT

Sr. No.	Village	Tehsil	Survey Number	Sub. Div. No.	Area		
					Ha.	Are	Sq.Mt.
1	2	3	4	5	6		
1	Tragadi	Mandvi	Govt		56	12	04
			Govt-237		02	79	85
			238		00	56	03
			239		00	82	58
			240		00	80	10
			241		00	32	54
			257		00	00	20
			258		00	07	20
			259		00	52	14
			Govt-260		01	28	43
			265		00	49	31
			270		00	02	30
			Govt-260		00	19	05
			261		00	00	20
			266		00	20	35
			Govt-260		00	11	89
			267		00	00	48
			219		00	72	24
			220		00	35	50
			218		00	47	14
			Govt-226		00	60	81
			201		00	57	04
			Govt-226		00	67	19
			200		00	34	72
			Govt-226		00	26	85
			Govt-197		00	00	20
2	Nana Bhadiya	Mandvi	River		00	52	29
			305	1	00	03	58

			Govt-553	P	00	53	72
			303		01	06	54
			304		00	03	68
			Govt-553	P1	10	65	25
			122		00	60	52
			121		00	75	52
3	Kandagara Mota	Mundra	Govt-379		00	01	99
			Road		00	07	55
			380		00	63	92
			385		00	50	00
			387		00	43	00
			388		00	10	89
			390	2	00	55	80
			390	1	00	33	10
			396		00	52	72
			395		00	09	36
			394		00	64	18
			393	1	00	04	81
			402	1	00	10	21
			393	3	00	53	97
			Road		00	07	44
			Govt-517	P	01	47	99
			489	3	00	06	22
			489	2	00	00	20
			Road		00	11	46
			Govt-517	P	00	09	17
			506		00	49	19
			507		00	38	11
			484	4	00	07	55
			484	3	00	00	20
			508	2	00	02	93
			508	1	00	27	56
			Govt-483	4	00	02	00
			483	3	00	15	51
			483	1	00	00	20
			483	2	00	02	82
			509		00	00	20
			482	3	00	13	69
			Govt-482	4	00	02	02
			Govt-482	2	00	00	20
			482	1	00	23	00
			Road		00	07	35
			27		00	11	92
			29	3	00	18	31
			26		00	01	06
			29	1	00	01	36
			29	2	00	11	53
			30	2	00	12	52
			29	1	00	34	40
			45		00	10	82
			32		00	51	22
			Govt-33	3	00	56	29
			33	1	00	37	16
			33	2	00	12	65
			River		00	38	63
			122	2	00	41	46
			Road		00	06	67
			121		00	47	47
			120		00	95	33

			Govt-517	P	00	49	24
			150	2	00	31	31
			150	1	00	09	63
			149		00	62	80
			Road		00	08	29
			148		00	65	09
			146		00	06	38
			147		00	85	69
			Govt-517	P	03	13	28
			159		00	37	92
4	Khakhar Moti	Mundra	213		00	35	04
			228		00	97	51
			227		00	61	12
			226		00	21	36
			Canal-233		00	20	50
			234		00	09	42
			235		00	13	37
			224		00	31	44
			223		00	35	73
			239		00	00	29
			CT		00	08	73
			222		00	52	45
			221		00	15	61
			241		00	39	93
			CT-528		00	15	36
			105		01	39	38
			107		00	58	56
			106		00	32	34
			G Panchayat-99		00	01	81
			G Panchayat-97		00	70	22
			96		00	05	18
			98		00	19	98
			Gauchar-48		00	30	33
			88		00	24	70
			87		00	48	29
			86		00	45	49
			54		00	00	20
			50		00	50	91
			51		00	57	03
			CT-526		00	05	06
			53		00	06	40
			52		00	60	81
			41		00	41	35
			44		00	00	20
			43		00	16	95
			42		00	38	97
			32		00	59	08
			35		00	02	74
			34		00	49	02
			N.H.Road-520		00	20	38
			33		00	49	62
			460		00	63	19
			461		00	08	58
			459		00	39	50
			458		00	57	32
			456		00	55	37
			463		00	00	20
			Govt-455		00	54	39
05	Desalpar	Mundra	405		00	60	33
			Govt-570	P	00	08	03

			430	1	01	09	97
			430	2	01	00	80
			423		00	68	40
			424		00	31	68
			429		00	54	44
			428		00	44	93
			Govt-570	P	02	02	06
			13		00	69	52
			C.T		00	04	55
			18		00	00	20
			14		00	51	95
			15	1	00	49	28
			15	2	00	33	91
			Govt-570	P	02	37	93
			51	2	00	00	20
			52	2	00	00	20
			55		00	03	90
			Govt-570	P	00	02	99
			Govt-97	-	01	08	99
			99	-	00	41	92
			Govt-570	P	00	25	57
			100		00	89	50
			C.T.		00	06	88
			132		00	41	93
			131		00	52	81
			121		00	54	49
			122		00	34	19
			123		00	28	57
			124		00	68	26
			C.T.		00	05	18
			River		01	44	29
6	Gelada	Mundra	382		00	53	94
			Govt-383		00	10	90
			Govt-384		00	26	69
			C.T-412		00	04	44
			Govt-387		00	08	51
			389		00	28	45
			388		00	19	69
			Gauchar-378		01	61	01
			379		00	00	20
			Govt-376		00	18	62
			375		00	42	63
			Road -410		00	08	78
			309		00	03	29
			350		00	66	85
			349		01	10	43
			311		00	55	75
			312		00	42	76
			347		00	02	76
			313		00	77	05
			Govt -314		00	69	38
			317		00	21	34
			316		00	97	53
			315		00	28	25
			Govt-321		00	59	60
			Nala-414		00	16	26
			322		01	05	08
			323		00	86	92
			242		00	07	58

7	Moti Bhujpar	Mundra	423		01	01	97
			424		00	20	37
			713	47	00	77	04
			713	18	00	47	26
			713	16	00	09	32
			Gauchar-727		00	10	72
8	Pratappar – 2	Mundra	Govt-1	P	03	43	02
			1	6	00	82	37
			1	8	00	79	76
			Govt-1	P	00	21	74
9	Pragpar-2	Mundra	65	2	00	38	25
			Nala		00	11	05
			65	1	00	19	30
			Nala		00	23	45
			Govt-65	P	01	67	46
			32		01	43	02
			Govt-65	P	02	28	92
			Govt		03	66	96
10	Baraya	Mundra	24		00	42	62
			23		00	42	95
			Gauchar -22		01	52	68
			17		00	17	29
			Road-506		00	12	33
			14		00	37	74
			13		00	11	36
			Road-504		00	12	46
			Gauchar -141		00	42	91
			River-513		00	84	13
			156		00	03	10
			Canal-509		00	13	20
			Gauchar-160		01	46	17
			Road-502		00	08	66
			Road/Gauchar 231		00	07	41
			238		00	37	54
			237		00	49	21
			Road-489		00	07	05
			244		00	78	30
			246		00	43	32
			247		00	27	96
			248		00	00	61
			330		00	00	44
			328		00	05	09
			Road-491		00	11	90
			327		00	09	03
			326		00	11	01
			325		00	30	66
			324		00	21	48
			323		00	21	42
			322		00	21	54
			317		00	00	76
			321		00	04	01
			320		00	01	46
			Govt-318		00	46	87
			319		00	33	76
			Road-492		00	10	42
			Govt-277		00	00	27
			276		00	34	12
			278		00	16	44
			280		00	40	79
			Govt-281		00	63	49

			284		00	78	41
			285		00	60	24
			286		00	38	55
			287		00	56	36
			288		00	04	20
			293		00	32	66
			289		00	01	31
			292		00	85	63
			291		00	32	56
11	Pragpar-1	Mundra	218		00	41	78
			219		00	54	50
			229		00	46	66
			232		00	20	69
			230		00	00	20
			231		01	04	57
12	Toda	Mundra	River-44		00	76	61
			Govt- 6		01	13	41
13	Viraniya	Mundra	Gauchar-352		00	24	05
			Road-419		00	07	35
			Gauchar-351		00	67	44
			349		00	06	16
			Govt-348		00	02	17
			345		00	01	27
			346		00	44	40
			344		00	26	23
			343		00	22	00
14	Bhorara	Mundra	293		00	00	26
			290		00	64	39
			292		00	00	20
			291		00	00	20
			289		00	33	31
			C.T-317		00	11	68
			282		00	00	20
			283		00	11	08
			288		00	23	53
			287		00	30	09
			286		00	03	99
			C.T-317		00	02	89
			318		00	45	90
			319		00	32	83
			320		00	38	94
			321		00	13	93
			356		00	93	25
			357		00	00	20
			355		00	25	76
			354		00	25	45
			353		00	52	90
			352		00	46	73
			349		00	45	95
			348		00	61	75
			346		00	00	20
			347		01	22	09
			344		00	09	30
15	Gundala	Mundra	528		00	81	40
			529	1	00	56	68
			530		00	59	07
			531		00	26	71
			542		00	03	29
			544		00	61	84

			543	2	00	46	66
			C.T.		00	14	40
			550	2	00	19	73
			551		00	25	25
			550	1	00	06	47
			N.H.Road-550	1P1	00	25	11
			550	1	00	25	42
			552		00	15	57
			549		01	03	45
			554		00	04	11
			Canal	-	00	07	44
			Canal-562	P2P2	00	01	52
			Canal-561	P1P2	00	17	67
			561		00	35	53
			C.T.		00	04	09
			555	1	00	71	52
			Road-555	1	00	07	89
			555	1	00	20	04
			555	2	00	04	18
			C.T.		00	06	43
			4	1	00	35	15
			4	2	00	14	96
			5		00	47	25
			6		00	55	51
			7		00	44	05
			Road-7		00	12	86
			7		00	08	74
			Govt-585	P	00	63	36
			94	2	00	15	82
			97		00	28	01
			C.T.		00	08	67
			133		00	61	81
			132		00	70	18
			Road		00	16	51
			138		01	26	68
			Govt-585	P	00	07	89
			201		00	24	29
			200		01	18	69
			199		00	58	23
			198	1	00	18	27
			198	2	00	15	96
			Govt-585	P	00	63	51
			198	3	00	03	26
			194		00	30	22
			193		00	15	21
			210	2	00	43	53
			210	1	00	17	08
			Govt-585	P	00	88	11

[F. No. R-12031/2/2018-OR-1/E-26406]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जून, 2022

का.आ. 608.—केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एनएचपीसी लिमिटेड के दिबांग बहु-उद्देशीय परियोजना, मायो सेक्टर-1, पोस्ट-रोइंग, जिला-लोअर दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश-792110 जिसके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 11011/01/9/2022-हिंदी]

विशाल कपूर, संयुक्त सचिव (रा.भा.)

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 21st June, 2022

S.O. 608.—In pursuance of Sub Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notify the Dibang Multipurpose Project, Mayu Sector-1, Post-Roing, Distt.-Lower Dibang Valley, Arunachal Pradesh-792110 of NHPC Limited under the administrative control of Ministry of Power, where 80% of the staff have acquired working knowledge of Hindi.

[F. No. 11011/01/9/2022-Hindi]

VISHAL KAPOOR, Jt. Secy. (O.L.)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

का.आ. 609.—केंद्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को राजपत्र में अधिसूचित करती है:—

1.	भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय, कोयंबटूर (चेन्नई क्षेत्र के अंतर्गत)
----	---

[फा. सं. ई-11011/1/2008-हिन्दी(321924)]

सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 14th June, 2022

S.O. 609.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office under the administrative control of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Food & Public Distribution), whereof more than 80% of staff have acquired the working knowledge of Hindi:

1.	Food Corporation of India Divisional Office, Coimbatore (under Chennai Region)
----	--

[F. No. E-11011/1/2008-Hindi(321924)]

SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

**रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)**

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2022

का.आ. 610.—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), राजभाषा नियम 1976 (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुसरण में **मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-145, नोएडा- 201306** जहां 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद्वारा अधिसूचित करता है।

[फा. सं. हिंदी 2018/रा.भा.-1/12/1]

डॉ. बरुण कुमार, निदेशक, (राजभाषा)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 27th April, 2022

S.O. 610.—Ministry of Railways (Railway Board) in pursuance of Sub Rule(2) and (4) of Rule 10 of the Official Language Rules, 1976 (use for the Official purposes of the Union) hereby, notify the Chief General Manager Office, Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd. Complex, Sector-145, Noida-201306 where 80% or more Officers/ Employees have acquired the working knowledge of Hindi.

[F. No. Hindi 2018/O.L-1/12/1]

Dr. BARUN KUMAR, Director (O.L.)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

का.आ. 611.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी.सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय नंबर, 2, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 07/1997) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16.06.2022 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/445/95-आईआर (सी-1)]

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 17th June, 2022

S.O. 611.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 07/1997) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No.2, DHANBAD as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of C.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 16.06.2022.

[No. L-20012/445/95 – IR (C-I)]

RAJENDER SINGH, Under Secy.

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2), AT DHANBAD****PRESENT** : Dr. S. K. Thakur, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act., 1947

REFERENCE NO 07 OF 1997**PARTIES:**

The Area Secretary,
Rastriya Colliery Mazdoor Sangh ,
House No. M-20, Sector IV, New MatiGarh Colony,
P.O. Nudhkurkee, Dhanbad .

Vs.

The Chief General Manager,
Block –II Area of Ms CCL
PO: Sonardih Dhanbad

Order No. L-20012/445/95-IR(C-I) dt.02.01.1997**APPEARANCES :**

On behalf of the workman/Union : None

On behalf of the Management : Mr. D. K. Verma, Ld. Advocate

State : Jharkhand Industry : Coal**Dated, Dhanbad, the 26th August, 2021****AWARD**

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Sec.10(1)(d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their **Order No. L-20012/445/95-IR(C-I) dt.02.01.1997**

SCHEDULE

“Whether the demand of the Union for promotion of S/Shri S.P. Srivastava and nine others (given below) In Grade ‘C’ in 1991 is justified? If so, to what relief is these workmen entitled?”

1. S/Shri Ramlgan Singh, 2. Keshwar Prasad 3. J. N. P. Sharma 4. Alaksh Narain Singh, 5 Dinesh Singh, 6. Anant Kumar 7. Anup Kumr Banerji, 8. Janardan Kumar Bimal. 9. Md. Ishlam Khan

1. On receipt of the **Order No. L-20012/445/95-IR(C-I) dt.02.01.1997** of the reference from the Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for adjudication of the dispute, it was registered as Reference case No. 07 of 1997 on 31.01.1997 and awaiting for Written Statement of Claim for filing by the Union which was filed on 04.08.1997 to enable the Tribunal to start proceeding.

2. Consequent upon filing of the written statement of Claim so staked by the Union on the matter under Reference the proceeding was set rolling before the Tribunal for proceeding .Ld. Advocate for the management also filed counter claim on the matter on behalf of the Management .With this matter advanced further for adjudication .In course of the hearing both sides exhibited documents in context of their respective claim and filed relevant documents out of which some stand exhibited whereas some remained unexhibited. Workmen side representation was not noticed since 30.04.2008. But proceeding abruptly stalled over evidence of the management which remain inconclusive till passing of this Award under Reference.

3. The brief fact of the matter as per written statement of claim filed by workman side is simply that the workmen concerned as per reference of the instant Industrial Dispute Case have not been prompted to higher Grade/Pay Scale despite they are eligible and entitled for such promotion.

4. Contrary to the claim of the workmen the Management side through their written statement –cum- rejoinder have put forward their justification for not promoting the concerned workmen to higher Grade with following submission/explanation

- I) The concerned workmen were promoted to Grade D during July to October, 1988 from their Grade E on the basis of recommendation made by Departmental Promotion Committee to fill up the Grade –III Post in Excavation Grade.
- II) For the purpose of adjudging suitability for promotion from Grade III workmen in excavation Cadre to Grade II workers, a Departmental Promotion Committee is constituted and a trade test are conducted. And after observing the results they are considered for their selection in order of merit by assessing Seniority, suitability and merit of the different candidates.
- III) As per existing number of vacancies in Grade C such number of excavation workers in Grade III are considered promoted to fill up such vacant posts. Accordingly to availability of vacancies in Grade C and considering all eligible candidates. The selection is made according to the different categories fixed for preparation of the list of such candidates in stratum. The Senior Most person in the list are selected and promoted and rest of the persons mentioned in the panel are not promoted.
- IV) The concerned workmen has not made any grievance against any Departmental Promotion Committee, violation of any Cadre Scheme, any grievance against any member of the DPC and any grievance on their suppression. The only grievance presently is for their promotion after completion of minimum eligibility period.
- V) The demand of the Sponsoring Union is obviously absurd and contrary to all the existing norms with regard to promotion of excavation worker in Grade III to Grade II and as such the demand is liable to be summarily rejected.

5. Against the counter submission made by Management side the workmen side has simply blamed the Management that the employer has adopted unfair labour practice by promoting undeserving junior candidates. It is wrong to suggest that employer followed any criteria in selecting workmen for promotion. The concerned workmen have always raised for violation of Cadre Selection i.e., that of against the Departmental promotion Committee.

6. Although witness from the Management side have been examined and cross examined but of any conclusive finding.

7. The Exhibited documents from the workmen side as available in the case file W-1 to W-3 are not relevant as they are the copies of Office Orders on regularization/promotion from one Grade to another. These do not substantiate their claim of any unfair labour practice by the Management.

8. The Management side has also filed list of documents copy of the office orders for promotion/regularization and dispute raised before Asstt. Labour commissioner (C) on regularization and promotion.

9. The witness and documents filed by the workmen side have not been able to substantiate their claim and counter to the submissions made by the management side. In that workmen side has not been able to prove that the Management does not follow any established norms for promotion through Departmental Promotion committee and that they have made any representation to the management against their non-promotion citing the copies of promotion orders filed and exhibited.

10. In contrast to the claim of the workmen, the Management has been able to prove their submission that the promotion are made on recommendation of the Departmental Promotion Committee after considering the required factors as Exhibited through the copies of promotion orders filed.

11. It has also been found the failure of the representation by the workmen side as the matter proceeded for ex-parte hearing. However, on representation of the workmen side, the Tribunal proceeded for hearing and evidence from both sides on 07.10.2002 again.

12. Despite giving opportunity to the workmen side for hearing the workmen side instead of proceeding ex-parte, the workmen side has failed to appear and represent in the proceedings after 2008. They remained absent also on the last date of hearing on 26.08.2021.

13. On the face of non-representation by the workmen side for more than 13 years on several dates of hearing despite giving opportunity to them and also notices issued through Registered posts and that the Tribunal does not think fit to interfere in the responsibility, duties, powers and function of the Departmental Promotion committee in the absence of any finding on malafide of the DPC, the claim of the workmen lacks merit.

14. Accordingly, it is decided that the workmen concerned with the instant Industrial Dispute Reference No. 07/1997 do not deserve any relief and so awarded no relief.

Dr. S. K. THAKUR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

का.आ. 612.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बी.सी.सी.एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय नंबर 2, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 49/1998) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16.06.2022 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/432/96-आईआर (सी-1)]

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 17th June, 2022

S.O. 612.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 49/1998) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, DHANBAD as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of B.C.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 16.06.2022.

[No. L-20012/432/96 – IR (C-1)]

RAJENDER SINGH, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2), AT DHANBAD

PRESENT : Dr. S. K. Thakur, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act., 1947

REFERENCE NO 49 OF 1998

PARTIES:

The Secretary,
Bihar Colliery Kamgar Union,
At: Jharnapara Hirapur,
PO: & Distt: Dhanbad. 826001

Vs.

The General Manager,
Govindpur Area No. III of M/s BCCL.
PO: Sonardih, Dhanbad - 826001

Order No. L-20012/432/96-IR (Coal-I) dt.20.02.1998

APPEARANCES :

On behalf of the workman/Union : Mr.D.Mukherjee Ld. Advocate .

On behalf of the Management : Mr. B. M. Prasad,, Ld. Advocate

State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 17th September, 2021

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Sec.10(1)(d) of the I.D. Act.,1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their **Order No. L-20012/432/96-IR (Coal-I) dt.20.02.1998**

SCHEDULE

“Whether the action of the General Manager, Govindpur Area No III of M/s BCCL, PO. Sonardih, Distt; Dhanbad in dismissing Sri S.R. Tiwari, Underground Munshi w.e.f. 10-/20.09.1974 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled to?”

1. On receipt of the Order No. L-20012/432/96-IR (Coal-I) dt.20.02.1998 of the reference from the Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for adjudication of the dispute, it was registered as Reference case No. 49 of 1998 on 16.03.1998 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the Registered Post to the parties concerned, directing them to appear before the Tribunal on the date fixed and to file their written statements along with the relevant documents.
2. Consequent upon registration of the Industrial Dispute as Ref. No. 49 of 1998 as referred by the Government of India vide its No. L-20012/432/96-IR(Coal-I) dated 20.02.1998 the case was set in rolling on with filing of the Written Statement and subsequent counter claim by the Management of Govindpur Area No. III of M/s BCCL, Dhanbad, on 15.06.1998 and 02.08.1999 respectively, which was followed by rejoinders. The matter advanced on merit after holding the domestic enquiry as fell short of fair and proper. But the proceeding came to halt over the evident of the Management since 01.09.2005. As evident from the record of the proceeding it went almost unrepresented by either side of the parties as barely made a few scanty appearances. Even after fresh revival attempt by the Tribunal failed to serve the purpose before it had closed for final order in the event of default so as to answer the Reference.
3. Neither the workman nor the Representative of the management appeared on fixed date 26.08.2021 to deal with issue relating to evidence of the Management hanging since long back with no sign of progress in sight. The case was fixed for hearing on merit on 26.08.2021 but both the parties remained absent as for all the past dates. Neither the parties nor their Ld. Advocates appeared for further proceedings in the case for past several dates. Sufficient opportunity was given to the parties to proceed with final hearing of the case but of no good.
4. It is apparently clear from the records that even after sufficient suo motu adjournments granted likewise on 24.06.2008, 30.04.2013, 27.06.2013 and 29.07.2013 on the same matter and, in fresh revival attempts on 18.04.2019 and 08.5.2019, no further proceeding could take place and, based on available facts and materials on record the hearing was concluded on 26.08.2021.

The case being belated one is related to alleged dismissal of the workman (S.R.Tiwari) by the Management of the General Manager, Govindpur Area No. III of the M/s BCCL seeking relief by the workman challenging the alleged action of the management through adjudication.

The case matter needs of paramount settlement as the matter was already placed twice before the Lok Adalat on 25.02.2008 and 27.5.2013 for out of Court Settlement but no fruitful result could be achieved nor did the matter move even an inch despite best efforts. Notable to mention here the Tribunal vide its order dt 01.09.2005 had declared the domestic enquiry so conducted against the workman by the Management null and void as the O.P./Management failed to prove the fact with any documents. Despite the same, the matter attributed to the sheer disinterestedness of the workman which led the Industrial Dispute as non-existent on merit whatsoever.

5. Having gone through the materials on record and lack of merits attributed to sheer disinterestedness of the workman in a stark contradiction to the fact that the Tribunal vide its order dt. 01.09.2005 declared the domestic enquiry conducted against the workman was not fair and proper as the O.P./Management failed to prove the alleged enquiry with relevant document. Despite above favourite position for workman was failed to take this situation to logical end for him getting relief. In such condition Tribunal has no alternative but to conclude that let this case be disposed of on the line of the decision that there exists no dispute between the parties at present.

6. With the Instant Industrial Dispute hovering over same issue for years together, there is no longer justification being felt to continue/sustain the proceedings specifically in the absence of appearances, as the case has been rolling out on the same status since 01.09.2005. The matter badly delayed deserves to be closed in the line of the natural justice in the light of ample adjournments granted suomottus over one stage and even fresh revival of the case on 18.04.2019 and on 08.05.2019 has almost proved of no use. The Industrial Dispute appears to have lost its merits or the footing on which issue has been raised. The dispute is thus disposed of accordingly as the Industrial Dispute by and between the parties is no more and as being treated as non-existent. The entire proceedings stand disposed of forthwith with no relief appears to be seeking for redressal from the Management.

Dr. S. K. THAKUR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

का.आ. 613.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बी.सी.सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण—सह—श्रम न्यायालय नंबर 2, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 109/1998) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16.06.2022 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/603/97-आईआर (सी-1)]

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 17th June, 2022

S.O. 613.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 109/1998) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No.2, DHANBAD as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of B.C.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 16.06.2022.

[No. L-20012/603/97 – IR (C-I)]

RAJENDER SINGH, Under Secy.

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2), AT DHANBAD****PRESENT** : Dr. S. K. Thakur, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act., 1947

REFERENCE NO 109 OF 1998**PARTIES:**

The Joint Area Secretary,
Bihar Colliery Kamgar Union,
Bhowra Colliery, PO: Bhowra,
Dhanbad

Vs.

The Chief General Manager,
Bhowra Area of M/s BCCL,
PO: Bhowra, Distt: Dhanbad

Order No. L-20012/603/97 I.R.(C-I) dated 13.04.1998**APPEARANCES :**

On behalf of the workman/Union : Mr. Dilip Chakraborty Union Representative

On behalf of the Management : None

State : Jharkhand**Industry : Coal****Dated, Dhanbad, the 28th March, 2022****AWARD**

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Sec.10(1)(d) of the I.D. Act.,1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their **Order No. L-20012/603/97 I.R. (C-I) dated 13.04.1998.**

SCHEDULE

Whether the demand of the Union for withdrawal of the degradation order of Shri Brij Bhushan Sharma, Dumper Operator, Bhowra OCP of M/s BCCL from Gr. B to Gr. C and for payment of the legal expenses pending with the Judicial Court in the criminal case connected with the accident is justified? If so, to what relief the workman is entitled?

2. On receipt of the **Order No. L-20012/603/97 I.R.(C-I) dated 13.04.1998** of the reference from the Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for adjudication of the dispute, it was registered as Reference

case No. 109 of 1998 on 23.04.1998 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices for 12.01.199 for further proceedings.

3. The matter proceeded with filing of claim by the workman side and countering the claim of the workman side by the O.P./Management along with relevant documents in support of their contention. During the proceeding deposition was also recorded by the workman and cross examined by the Management side. The proceeding remained stalled after 26.03.2008 and resumed only on 18.04.2019. No development for the proceeding is found available on record meaning thereby the workman side might have lost interest to proceed with their claim otherwise the matter would have taken up for hearing during gap of the more than eleven years. On 18.05.2019 on the date of resumed hearing after long gap Mr. Dilip Chakraborty, Area Secretary of the Sponsoring Union appeared and made submission that the concerned workman has already retired from service in the year 2002 and is not interested to proceed with hearing of the case any further.

4. Although the workman side was directed to file written petition to the effect of statement given by Area Secretary of the Sponsoring Union but no such petition in writing could be filed by the workman side. The matter was again taken up for hearing on 03.12.2019, 15.01.2020 and 26.08.2021 after issue of notices to both the parties for hearing in the matter. However, none appeared nor any representation received from the workman side in the matter. Similar was situation with the O.P./Management side.

5. Under the circumstances as narrated above when the workman side did not show interest in appearance or representing their case matter despite opportunities provided shows truthness to the statement given by the Area Secretary of the Sponsoring Union that the workman is not interested for further proceeding in the matter as he has already retired in the year 2002.

6. As such it can be safely concluded that the dispute as per reference Industrial Dispute No. 109/98 has lost its status as dispute to exist anymore and so deserves to be awarded as no claim and so no claim award is passed.

7. Let the copy of the Award be sent to the Appropriate Government as required under the Act for publication.

Dr. S. K. THAKUR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

का.आ. 614.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बी.सी.सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण—सह-श्रम न्यायालय नंबर 2, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 09/1998) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16.06.2022 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/398/96-आईआर (सी-1)]

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 17th June, 2022

S.O. 614.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 09/1998) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No.2, DHANBAD as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of B.C.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 16.06.2022.

[No. L-20012/398/96 – IR (C-I)]

RAJENDER SINGH, Under Secy.

ANNEXURE

THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2), AT DHANBAD

PRESENT: Dr. S. K. Thakur, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act., 1947

REFERENCE NO 09 OF 1998

PARTIES:

Jt. General Secretary,
Rastriya Colliery Mazdoor Sangh,
Rajender Path, Dhanbad.

Vs.

The General Manager,
Kustore Area of M/s BCCL,
PO:Kustore, Dhanbad .

Order No. L-20012(398)/96-IR(C-I) dt 31.12.1997

APPEARANCES :

On behalf of the workman/Union : None.

On behalf of the Management : Mr. U. N. Lal, Ld. Advocate

State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 28th March, 2022

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Sec.10(1)(d) of the I.D. Act.,1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their **Order No. L-20012(398)/96-IR(C-I) dt. 31.12.1997**

SCHEDULE

Whether the action of the Management of Kustore Area No. VII of M/s BCCL in dismissing Shri Satrugan Bouri, Miner/Loader w.e.f. 8-5-92 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?

2. On receipt of the **Order No. L-20012(398)/96-IR(C-I) dt 31.12.1997** of the reference from the Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for adjudication of the dispute, it was registered as Reference case No. 09 of 1998 on 27.01.1998 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the Registered Post to the parties concerned, directing them to appear before the Tribunal on the date fixed and to file their written statements along with the relevant documents. In pursuance of the said order, notices by the Registered Post were sent to the parties concerned for submission of claim statement as per provisions of the said reference.

3. The fact from the record transpires in the written statement of claim submitted by the workman through sponsoring Union that Satrugan Bouri, M/Loader was working at Ena Colliery under Kustore Area of M/s Bharat Coking Coal Ltd. on permanent vacancy. On account of his illness the workman stopped attending duty and remained absent for more than four months. As stated in the claim the Management initiated necessary proceedings and dismissed the workman from service w.e.f. 08.05.1992 even after unblemished service track of record against which this Industrial Dispute raised. As there were several irregularities found in conducting the said inquiry followed by several representations to the Local and Area Managements for the resumption of duty by the workman but of no use. In conciliation the Management did not allow the workman for resumption of duty which has resulted in failure of conciliation and subsequent birth of the Reference..The workman pray for resumption for duty with all consequential reliefs with fringe benefits from the date of dismissal.

4. Whereas the O.P./management counter claim in the petition stated that the present dispute of the workman are false, unfounded, improper and unjustified. With categorically denials of the claim point wise by the O.P./Management with specific statement that the workman was absenting from duty w.e.f. 21.1.1991 without any information or any sanctioned leave prior to absenting his duty which constitute the misconduct on the part of a workman. Further submission in the Written Statement of the O.P./Management is that the workman did not turn up to participate in the said enquiry either personally or through his representative which tantamount the wilful negligence of the workman as the workman was the habitual absentee. Due to his habitual absentism he was issued charge sheets earlier also dated 07.05.1990,19.06.1990 and 17.04.1991 for the same alleged charges for absenting from duty without any permission, leave and information to Controlling Authority .On each such occasion of proceeding on his request minor penalty was given on leniency and allowed him to continue in the service. So the workman is not entitled for any direction for resumption of duty as well as any relief like full wages from the date of dismissal.

5. The O.P./Management filed List of the documents enclosing therewith the documents as listed hereunder in their contention

- i) Xerox copy of the Charge sheet No. Ena/PD/CS/Abs/90/6252 dt.07.05.1990
- ii) Xerox copy of Note sheet by Dy.CME to the General Manager dated 19.06.1990
- iii) Xerox copy of the Charge sheet No. 667 dated 17.04.1991 S.O.M.,Ena to Shatrughan Bouri
- iv) Xerox copy of enquiry No. 749 dated 30.04.1991 by S.O.M., Ena to Shatrughan Bouri

- v) Xerox copy of Enquiry No. 2099 dt.23.10.1991 by Dy.C.M.E to Ena to the workman
- vi) Xerox copy of the letter dated 09.05.90 and 29.04.1991 by Shatrughan Bouri to M. Manager in two copies
- vii) Xerox copy of the letter dt.17.04.1991 by workman to P.O., Ena colliery.
- viii) Xerox copy of list of absentism of Attendance Register.
- ix) Carbon copy of the charge sheet dated 18.01.1992 by Agent to Shatrughan Bouri
- x) Xerox copy of enquiry proceedings and report regarding chargesheet No. 107 dt. 18.01.1992
- xi) Xerox copy of postal receipt to the Notice issued to workman by registered.
- xii) Xerox copy of Notice No. 409 dt.23.03.1992 by Agent to all concerned
- xiii) Xerox copy of the letter No. 6854 dated G-5/5/92 by GM, Kustore Area No. VIII, Shri Shatrughan Bouri with the copies to all concerned
- xiv) Xerox copy of list of dismissal workers No. 681 dt. 13.05.1992 by Agent Ena Colliery to all concerned.

6. No document relating to the case matter to counter the contention with documentary support of the Management was filed either by the workman or by the Union itself till closing of hearing in this Case.

7. Ever since 2015 the representation of the workman was not noticed as workman did not take any initiative nor he was able to substantiate his contention stopped participating into the proceedings in regular course.

8. As the workman side failed to represent since 2015 in regular course of hearing the Tribunal finds no need to go further in interfering the matter of the cause of action under Sec. 11- A of the I.D. Act 1947 which apparently show that either the workman has no point to prove his claim or workman is not interested to contest on merit. The Tribunal does not find any merit in the claim of the written statement of claim as made out by the workman in the background of the submissions made by the Management with documentary evidences. Under the facts and materials available on record there is no convincing evidence /materials of the Union/petitioner for which the claim could be held justifiable. The conduct and gesture and inaction on the part of the workman for last several years assume significance that the workman lost the interest to proceed with the case.

9. In view of the above foregoing factual position, the Tribunal is constrained to hold that adjudication is not pending any more, when the petitioner is no longer interested. The Industrial Dispute between the parties to this case has turned meritless. So the instant proceedings stands disposed of by virtue of sheer reluctance of the workman. Notably the workman does not qualify to get any relief in the instant Reference No. 09-1998 and so awarded no relief.

Dr. S. K.THAKUR, Presiding Officer